

## प्रमुख नीति - निर्देशक तत्व

संविधान की धारा 38 से 51 तक में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अध्ययन की दृष्टिकोण से नीति - निर्देशक तत्वों को निम्न-लिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:-

### आर्थिक सुख और सामाजिक हित संबंधी

निर्देशक तत्व - नीति-निर्देशक तत्वों का प्रमुख लक्ष्य एक लोक कल्याणकारी राज्य (Public Welfare State) की स्थापना करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नीति - निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है।

- (1) अनुच्छेद - 38 नीति-निर्देशक तत्व राज्य को निर्दिष्ट करता है कि वह लोककल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो।

44वें संविधान संशोधन द्वारा 38(2) अनुच्छेद जोड़कर एक नया निर्देशक तत्व शामिल किया गया है, जो यह उपसन्धित करता है कि, राज्य विशेष रूप से आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल अक्षयता बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले एवं विभिन्न अवसरों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेगा।

(ii) राज्य प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करेगा।

(b) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बँधे हो, जिससे अल्पसे अल्प लोगों का सर्वाधिक हित हो सके।

(c) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार हो, जिससे जन और उत्पादन - साधनों का सर्वसाधारण के लिए अधिकारी संकेन्द्रण न हो।

(d) स्त्री और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन हो। (Equal pay for equal work)

(e) स्त्री और पुरुष कर्मचारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की बालभावना का दुुरुपयोग न हो।

(f) बालकों को स्वतंत्र और गरिमायुक्त वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाय।

(iii) राज्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए, निःशुल्क अग्रणी सहायता की व्यवस्था करेगा।

(iv) अनुच्छेद 41 के तहत राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने का, शिक्षा देने और बेकारी, बुढ़ापा, विमारी और निश्चिन्ता की दशाओं में लोक सहायता देने का अधिकार से संबंधित करे।

(v) अनुच्छेद - 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रकृति सहायता उपबन्ध करने का प्रावधान है।

(vi) अनुच्छेद - 43(क) राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपकरणों, संस्थाओं या अन्य संगठनों के प्रयास से किसी अन्य विधि से विशेष कदम उठाएगा।

## गौ-जीवादी सिद्धांत-

- (i) अनुच्छेद-40 राज्य, ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वयंसेवा ग्रामन इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।
- (ii) अनुच्छेद-43, राज्य, गाँवों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ावा देगा।
- (iii) अनुच्छेद-46, राज्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों की विशेष साधनों से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्धकार और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।
- (iv) अनुच्छेद-47, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य सुधारों का प्रयास करे। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाये।
- (v) अनुच्छेद-48- राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों पर संगठित करने का प्रयास करेगा। विशेषकर गाँवों और कस्बों तथा अन्य पुराने पशुओं के सुधार तथा उसके क्षेत्र के प्रतिबंध हेतु राज्य विशेष कार्य प्रारंभ करेगा।
- (vi) अनुच्छेद-48 (A) इसे 42वें संशोधन द्वारा वर्ष 1978 में जोड़ा गया है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करना तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना।

उदारवादी सिद्धांत - नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत उदारवादी सिद्धांतों को भी अपनाया है, जो इस प्रकार हैं :-

- (i) अनुच्छेद-44 - (समान नागरिक संहिता) राज्य, भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
- (ii) अनुच्छेद-45, राज्य, 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक सभी बालकों के लिए, प्राथमिक बालभावस्था की देख-रेख, पोषण एवं शिक्षा देने के लिए उपकल्प करने का प्रयास करेगा।
- (iii) अनुच्छेद-50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से प्रथमकरण।
- (iv) अनुच्छेद-51 - अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुख को बढ़ावा देना।

प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निर्देशक तत्व -  
अनुच्छेद-49 - राज्य प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थानों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा करेगा।